RIGHT TO FOOD MEET

Use targeted PDS to help those hit by drought: NHRC chief

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 28

THE CHAIRPERSON of the National Human Rights Commission (NHRC), Justice H L Dattu, Thursday suggested that with 254 districts in the country reeling under drought, the targeted public distribution scheme should be used to ensure food for all in these areas.

"How can we provide foodgrain using the Targeted Public Distribution System (TPDS) to a large section of society reeling under the effect of drought, as a short-term and long-term strategy, also needs to be made part of the discussion with reference to right to food and national food security act," Dattu said.

He added that "the issue of crop rotation to conserve our soil and water levels as well as our food requirements needs to be addressed with a missionary zeal".

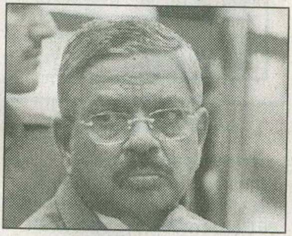

NHRC chairperson HL Dattu

Speaking at the inaugural session of the two-day national conference on the right to food organised by the NHRC, Dattu said, "It pains to know that 15 per cent of food worth Rs 92,000 crore per year is wasted during production, harvesting, transportation and storage, as per a study carried out under the Union Ministry of Food Processing Industries. Food security has to be read and studied with our agricultural practices and the challenges facing them in the wake of falling groundwater levels at a rapid speed causing an alarming situation of drought in several districts of the country."

The conference entailed discussions on the scope of the National Food Security Act (NFSA), 2013 and the obligations of the Centre and the states to ensure food security, nutritional support to women and children and implementation of the NFSA.

"The ultimate goal of NFSA with various social welfare schemes should be that nobody should fall prey to begging for food," said Dattu.

He said there is no dearth of policy and programmes for ensuring food for all, adding that ensuring the implementation of these schemes was as much the responsibility of citizens as it was of the government.

"Pointing fingers at the government machinery may not be correct all the time. People themselves need to become a watchdog of the welfare schemes instead of falling prey to the allurement of pilferage. They must stop thinking about the government as a separate entity from them," Dattu said.

Ganga to be clean by July 2018: Uma

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 28

MINISTER FOR Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Uma Bharti Thursday vowed to clean the Ganga by July 2018.

Responding to a volley of queries during Question Hour in Lok Sabha, Bharti argued that even packaged mineral water, if put through proper laboratory tests, could be found to fall short of the benchmark. Therefore, the bar for judging the purity and rejuvenation of Ganga water would be the return of aqua-life in the river, she said. This, she underscored, means a return of river dolphins, turtles and goldfish to stretches of the river where they existed earlier.

She said a consortium of experts drawn from the IITs had been assigned the task of preparing the aqua project.

Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav suggested that urban drainage systems should be reworked to ensure that all waste go to the fields, and not end up in rivers. He said it would provide farmers with fertiliser and save rivers from pollution. This prompted Bharti to request Yadav to tell his son, UP Chief Minister Akhilesh Yadav, to issue no-objection certificates to two of her ministry's projects in Mathura and Vrindavan.

Her remarks had an immediate effect, as Yadav was seen gesturing her to come to his side. She did so and sat down with him and wrote a small note for his reference.

FAMILY MAN

A child guards his family's water containers kept in a queue for potable water at a makeshift camp in Mumbai on Thursday. Some 300 families who have migrated from the drought affected Marathwada region are camped at a municipal ground in the city. ■ afp

Uma Bharti, Mulayam lock horns over pending Ganga clean-up plan

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Ganga rejuvenation minister, Uma Bharti, and SP chief, Mulayam Singh Yadav, on Thursday engaged in a verbal duel, with Bharti accusing the SP-led UP government of sitting on the Ganga clean-up plan.

The Ganga is one of the most polluted rivers in India.

According to a report published by New Delhi-based think tank Centre for Science and Environment two years ago, the installed capacity of sewage treatment plants for the Ganga was 1,208 mega litre per

Uma Bharti, Mulayam Singh

day (MLD) whereas the official sewage load in the river was 2,723MLD.

The war of words between the two leaders began in Lok Sabha when the minister blamed the Congress for the pollution of the river.

She said it was an outcome of the "sins committed by the Congress in the last 70 years."

Responding to her statement, Yadav said the situation would remain unchanged unless measures are taken to prevent pollutants from mixing with the river.

"Dirty drains that are (sic) entering the river should be diverted to the farm lands," Yadav said.

Bharti retorted to Yadav's 'suggestion', saying, "Despite my efforts, the UP chief minister has not found time to meet me. The project is pending for three months. You could ask your son to clear the project expeditiously," she told Yadav.

BAKED EARTH

A couple from Jhap village, about 60 km from Ahmedabad, fetch drinking water from a kilometre away. *Javed Raja*

नदियों का सम्मान करो तभी जल बच सकेगा: शंकराचार्य

मेरठ | हिन्दुस्तान टीम H29 P-12

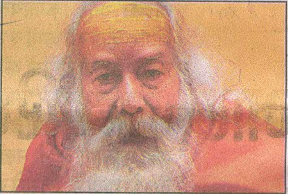

शंकराचार्य स्वामी स्वरुपानन्द महाराज ने हिन्दुस्तान द्वारा जल संकट को लेकर चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समय लोगों को जल की महत्ता बताना जरूरी है, जल अमृत है, लेकिन वर्तमान में लोग इसकी महत्ता को भूल रहे हैं।

नदियों पर बांध बनाकर उन्हें बांधा जा रहा है, नालों और कारखानों का गंदा पानी नदियों में डालकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। यदि अभी भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिनों में पानी पर बड़ा युद्ध होगा। हमें नदियों को खुला छोड़ना होगा और उन पर बने बांध हटाने होंगे। गंगा का पानी अमृत है, गंगा में जो भी नदी मिलती है उसका पानी अमृत हो जाता है। हमें सभी नदियों का सम्मान करना होगा। यदि नदियों को अपमानित किया जाता रहा तो जल संकट और बढ़ेगा।

and documented at Bhagirath(English) & Publicity Section, CWC.

नमामि गंगे | केंद्र का दावा, जुलाई 2018 में होगा गंगा की निर्मलता का ऐलान

कछुए, मछलियां होंगी तब ही गंगा निर्मल

29-NBT-P11

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने कहा कि गंगा नदी की निर्मलता की प्रमाणिकता किसी लैब की रिपोर्ट नहीं, बल्कि नदी में रहने वाले कछुए और मछलियां होंगी। सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया है कि जुलाई 2018 में गंगा नदी की निर्मलता का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा को निर्मल बनाने के पहले भी कई प्रयास हुए हैं, लेकिन अब एनडीए सरकार ने समग्रता के साथ गंगा नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी को साफ करने

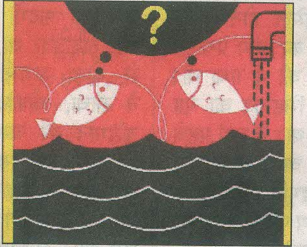

के लिए केंद्र सरकार की ओर से 20,000 करोड़ रुपये की जो फंडिंग की गई है, उसमें से 350 करोड़ रुपये जागरूकता फैलाने के लिए रखे गए हैं। उमा ने कहा कि गंगा नदी साफ हुई है या नहीं, इसका फैसला मिनरल वॉटर की जांच की तरह नहीं होगा, बल्कि इसका सबूत कछुए और मछली जैसे जीव होंगे। अगर ये जीव गंगा नदी में हैं तो हम मान लेंगे कि नदी निर्मल है। उन्होंने कहा कि गंगा को साफ करना 70 साल का हमारा प्रायश्चित है।

गंगा आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण : उमा

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि यमुना, गोमती आदि नदियों की निर्मलता का अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि गंगा को सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंगा पर 50 लाख लोगों की आजीविका निर्भर करती है।

मुलायम का सुझाव माना

मुलायम सिंह गुरुवार को एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री की तरह ही लोकसभा में नजर आए। प्रश्नकाल के दौरान जब उमा भारती गंगा की सफाई से जुड़े सवालों का जवाब दे रही थीं, तभी मुलायम सिंह खड़े हो गए और उन्होंने सुझाव दे डाला कि गंगा को सफाई करने का एक आसान तरीका यह है कि जितनी नालियां, नाले गंगा में गिरते हैं, उनका मुंह खेतों की ओर मोड़ दीजिए। इससे खेतों को खाद भी मिलेगी और गंगा नदी भी प्रदूषित होने से बच जाएगी।

परियोजनाएं तैयार — उत्तर प्रदेश सरकार चार माह से इसे मंजूरी नहीं दे रही

नदियों की सफाई पर उमा ने मुलायम को दिखाया आइना

नई दिल्ली, (भाषा): लोकसभा में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के नदियों को साफ करने के सुझाव पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने उनसे शिकायत की कि मथुरा और वृंदावन से जुड़ी परियोजनाएं पिछले चार महीने से तैयार हैं और उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव नीत सपा सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नदियों के प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण नालों के माध्यम से शहरों की गंदगी नदियों में प्रवाहित किया जाना है। अगर इन नालों के माध्यम से गंदगी नदियों में नहीं गिरे और इन्हें खेतों की ओर मोड़ दिया जाए तो यह खेतों के लिए

भी फायदेमंद होगा। हालांकि इस दौरान भाजपा के कुछ सदस्यों को यह कहते सुना गया कि बेहद प्रदूषित गंदे जल से खेतों को नुक्सान होगा। बहरहाल, उमा भारती ने शिकायत भरे लहजे में कहा कि मुलायम सिंह यादव उनके बड़े भाई समान हैं, वह उनसे कहना चाहती हैं कि मथुरा, वृंदावन के लिए योजना पिछले चार महीने से तैयार है लेकिन अखिलेश यादव सरकार इसे मंजूरी नहीं दे रही है। कल बैठक कराइये और इसे आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करिए। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और नदी की जलीय जीवन व्यवस्था को बहाल करते हुए जुलाई 2018 तक गंगा को निर्मल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा में कई सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रतिबद्धता से कदम उठाया और नमामि गंगे योजना के जरिये 100 प्रतिशत केंद्र वित्त पोषण के माध्यम से इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

काठा नदी को जीवित करने निकल पड़े गांव वाले

जल संरक्षण के लिए 20 दिन चले हिन्दुस्तान के बिन पानी सब सून अभियान के अंतिम पड़ाव पर सकारात्मक नतीजों की शुरुआत हो चुकी है। शामली में काठा नदी को पुनर्जीवित करने का मलकपुर के लोगों का संकल्प यही दर्शाता है। तमाम संगठनों और धर्मगुरुओं के साथ आने से उम्मीद है कि हमारी छोटी-सी पहल जल्द ही कुछ बड़े नतीजे लाएगी। यकीन मानिए, हमारी पहल और आपके संकल्प की यही छोटी-छोटी बूंदें आने वाली पीढ़ियों के लिए ढेर सारा पानी संजोकर रखेंगी।

शामली | वरिष्ठ संवाददाता

मलकपुर के ग्रामीणों ने गुरुवार को 170 साल से मृत काठा नदी को एक किलोमीटर लंबी झील में तब्दील करने करने का संकल्प लिया। हिमालयन कम्युनिटी कालेज के प्राचार्य उमर सैफ के नेतृत्व में ग्राम प्रधान और ग्रामीण फावड़ा लेकर नदी की ओर निकल पड़े। उन्होंने घंटों श्रम करके जमीन को समतल करने की शुरुआत की।

घंटों तक पसीना बहाने के बाद उमर सैफ ने बताया कि कभी इस नदी में बेइन्तहा मगरमच्छ और घड़ियाल रहते थे। पानी न होने से लोगों ने जमीन दबा ली और खेती भी करने लगे। पिछले 170 सालों में सरकार ने कभी इसे जीवित करने की ओर ध्यान नही दिया। अब लोगों ने ये शुरुआत की है और इसकी जीआईएस मैपिंग कराई और इसमें रहने वाले जीव जन्तुओं का अध्ययन कराया। जल्द ही उसकी रिपोर्ट भी पेश करेंगे।

अभी काठा नदी का मात्र एक किलोमीटर लंबा टुकड़ा जीवित करने की मुहिम शुरू की गई है। योजना ये है कि इसके आसपास बहने वाले बारिश के पानी को जमा किया जाए। बाद में सोलर ट्यूबवैल भी लगवाएंगे, ताकि गर्मियों में यहां रहने वाले जीवों को पानी मिलता रहे। अगर ये परियोजना सफल रही तो लगभग 90 किलोमीटर लंबी एक मीठे और साफ जल की नदी जीवित हो उठेगी। मलकपुर के ग्राम प्रधान आनंद सैनी एवं ग्रामीण भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। ग्राम प्रधान आनंद सैनी का कहना है कि इसके लिए जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन का हर स्तर पर सहयोग लिया जाएगा।

शामली के मलकपुर में गुरुवार को काठा नदी को झील में तब्दील करने के लिए खुदाई करने में जुटे ग्रामीण। • हिन्दुस्तान

1830 से सूखी नदी

काठा नदी शिवालिक पर्वत से निकली थी। 1830 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कराया तब सहारनपुर और रामपुर के बीच नहर बनाने के लिए इस नदी के शिवालिक से आने वाले स्रोत को रोक दिया गया था। तब से लगभग 150 किलोमीटर लंबी नदी मृत पड़ी है।

90 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की झील बनाने की योजना

- लोगों ने सरकार से मांग की है कि बरसात के दिनों में जब पानी ज्यादा होता है तब पूर्वी यमुना नहर का पानी इसमें छोड़ दिया जाए जिसे चेक डैम बनाकर जमा कर लेंगे और पूरे साल उस पानी से काम चलाएंगे।
- इस पर एक लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की परियोजना विभाग ने बनाई भी है मगर वह मंत्रालय में लटकी पड़ी है।
- जल लाने पर इसके अंदर यमुना नदी में रहने वाले सभी जीवों और पौधों का पुनर्वास किया जाएगा और अन्त में इसे घड़ियाल सेंचुरी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- काठा नदी के दोनों और वन विभाग की भूमि है जिस पर विभाग से बात की है नदी के दोनों किनारों को बटरफलाई पार्क के रूप में विकसित किया जाए। इस तरह एक मर गए इकोसिस्टम को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

70 साल पुराना कुआं जिंदा होगा

लखनऊ। चौपटिया में 70 साल पुराने कुंदन लाल के ठाकुरद्वारे का कुआं ठंडा पानी देगा। 20 साल से इस कुएं का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। 'हिन्दुस्तान' की पहल पर इस कुएं को जीवन देने के लिए कुछ समाजसेवी आगे आए हैं। मंदिर के व्यवस्थापकों और इलाके के लोगों ने इस कुएं की सफाई की। मंदिर की छत से पाइप को कुएं के पास लाया जाएगा। यहां एक तीन फुट का चैंबर बनाकर उसमें जाली लगाई जाएगी। चैंबर में कोयला, ग्रेविल और मौरंग डाली जाएगी जिससे छत से आने वाला बारिश का पानी साफ होकर कुएं में जाएगा।

30 दिन में तालाब खोदेंगे

आगरा। आगरा-मथुरा की सीमा पर मौजूद गांव जोधपुर झाड़ में 30 दिन में तालाब का काम पूरा कर दिया जाएगा। बुधवार को डीएम पंकज कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। 15 मई से काम शुरू होगा और एक महीने में तालाब खोद दिया जाएगा। 'हिन्दुस्तान' में जोधपुर झाड़ का मामला छपने पर प्रशासन ने इस गांव को गोद ले लिया था।

तालाब को खुदवाया

मुजफ्फरनगर। बिन पानी सब सून अभियान के तहत गुरुवार को लुहारी खुर्द में पूरी तरह से पाटे जा चुके एक तालाब को तहसीलदार सदर ने जेसीबी मशीन से खुदवाया। नगर पालिका ने टैंकर से छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया है। सहारनपुर में गुरुवार को हिन्दुस्तान में टीम ने नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में हो रही पानी की बर्बादी को रुकवाया।

पानी बचाने की शपथ ली

बिजनौर। नांगल सोती में मंदिर से लाउडस्पीकर से लोगों से पानी बचाने की अपील की गई। जिले में पानी की कीमत समझने और उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए वीएसडी, नांगल सोती, चंदक, नजीबाबाद के धामपुर, स्योहारा, नूरपुर और चांदपुर के स्कूलों में अध्यापकों ने बच्चों को पानी बचाने की शपथ दिलाई।

प्यास बुझा रहे कमलेश

सासाराम। शहर के सपुल्हगंज काजीपुरा मोहल्ले के कमलेश कुमार रोजाना अपनी जेब से 100-150 रुपये खर्च कर 300 लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। इलाके के लोगों के लिए कमलेश किसी फरिश्ते से कम नहीं, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण चापाकल सूख गए हैं। कमलेश रोजाना तीन घंटे तक जेनरेटर से मोटर चलाते हैं।

प्राचीन कुंडों का जीर्णोद्धार

मथुरा। जिले के प्राचीन 10 कुंडों के जीर्णोद्धार दो करोड़ रुपये लागत से कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में ब्रज में प्राचीन काल के 50 कुंडों के जीर्णोद्धार कार्य का प्रस्ताव तैयार किया गया था। पहले चरण में 10 कुंडों का जीर्णोद्धार कार्य हो चुका था। दूसरे चरण के 10 कुंडों का काम होगा।

12.50 लाख लीटर पानी बचाया

रांची। झारखंड में पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' के 'जल रिपोर्टर' शहर-शहर निकले। कोल्हान में 'हिन्दुस्तान' की जल सेना साढ़े बारह लाख लीटर पानी की बर्बादी रोकने में सफल रही है। पूर्वी सिंहभूम में साढ़े छह लाख लीटर पानी बर्बाद होने से रोका।

गंगा को 2018 तक निर्मल बनाएंगे : उमा

लोकसभा में गुरुवार को कई सदस्यों के प्रश्नों पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए केंद्र ने प्रतिबद्धता से कदम उठाया है। जुलाई 2018 तक गंगा को निर्मल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

ब्योरा पेज 18

उमा भारती ने पूरक प्रश्नों पर दिए जवाब, नदी की जलीय जीवन व्यवस्था को बहाल करने पर जोर

गंगा नदी को 2018 तक निर्मल बनाएंगे

लोकसभा

नई दिल्ली | एजेंसियां

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। नदी की जलीय जीवन व्यवस्था को बहाल करते हुए जुलाई 2018 तक गंगा को निर्मल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

लोकसभा में कई सदस्यों के पूरक प्रश्नों पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए केंद्र ने प्रतिबद्धता से कदम उठाया है। नमामि गंगे योजना के जरिये 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ सरकार इसे आगे बढ़ा रही है।

इसके तहत 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही जन जागरूकता फैलाने के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मंत्री ने कहा, इसके साथ हमारा प्रयास है कि गंगा में डालफिल, कछुए, स्वर्ण मछली समेत विभिन्न जलीय व्यवस्था को बहाल किया जाए। उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी पर करोड़ों लोग आजीविका के लिए निर्भर हैं। हालांकि हमने गंगा को आस्था की नजर से ही देखा है। अब हम गंगा को आर्थिक दृष्टि से संजोने की योजना पर काम कर रहे हैं। इन समग्र प्रयासों से हमारा लक्ष्य जुलाई 2018 तक गंगा को निर्मल बनाने का है।

गुरुवार को संसद सत्र के बाद सदन से बाहर आतीं जल संसाधन मंत्री उमा भारती। • हिन्दुस्तान

सहयोगी नदियों की सफाई

मंत्री ने कहा, गंगा तब तक निर्मल नहीं हो सकती जब तक इसकी सहयोगी नदियां साफ नहीं होंती। इन नदियों में उद्योगों की गंदगी मिलती है। इसलिए गंगा के साथ यमुना, राम गंगा, गोमती, सरयू की निर्मलता का अभियान चलाया जाएगा। गंगा के साथ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में गंदगी फैलने को लेकर हम चिंतित हैं।

क्या पहल की

उमा भारती ने कहा कि वन शोध संस्थान ने गंगा नदी के इर्द गिर्द वृक्षारोपण के लिए 1600 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने के लिए भी पहल की गई है। इसके अलावा सात मंत्रालयों के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

'बड़े भाई साहब' से मदद मांगी

नई दिल्ली। गंगा की सफाई के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने अपने 'बड़े भाई साहब ' से मदद मांगी है, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद उन्हें 'भतीजा' और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैठक के लिए समय नहीं दे रहे हैं। इसलिए गुरुवार को उमा भारती ने अपने बड़े भाई साहब मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव के साथ बैठक कराने का आग्रह किया।

लोकसभा में गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के बारे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने जल संसाधन मंत्री को कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि गंदी नालियों को खेतों की तरफ मोड़ दें। इससे जमीन उपजाऊ हो जाएगी और गंगा भी साफ हो जाएगी। वर्ष 1952 में डॉ. राममनोहर लोहिया ने यही बात सदन में रखी थी। इसके अलावा गंगा साफ करने का कोई रास्ता नहीं है।

उमा भारती ने फौरन इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि मथुरा-वृंदावन परियोजना चार माह से तैयार है। वह रोज अखिलेश यादव को फोन करती हैं। बैठक तय हो जाती है, कभी मुख्य सचिव कह देते हैं, वह नहीं हैं कभी मुख्यमंत्री कह देते हैं वह नहीं हैं। इसलिए भाई साहब से मेरा निवेदन है कि वह फौरन अखिलेश यादव के साथ बैठक कराकर परियोजना को एनओसी दिलवाएं। **(वि.सं.)**

ऋषिकेश में पोस्टर बनाकर विश्व रिकार्ड बनाया

ऋषिकेश पब्लिक स्कूल (आरपीएस) ने एक बार फिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। एक साथ दो हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं और स्टाफ सदस्यों ने पांच हजार से अधिक पोस्टर बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। पोस्टर के जरिये गंगा संरक्षण का संदेश दिया गया। गुरुवार को ऋषिकेश पब्लिक स्कूल के परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बच्चों ने 18 अप्रैल 2015 को गंगा संरक्षण थीम पर ही लगभग डेढ़ किमी रंगोली बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था।

राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उत्पादन बढ़ा तो मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में घटा

RP.29-P-12

आधे से अधिक राज्यों में सूखे से जल विद्युत उत्पादन घटा

अनिल अश्विनी शर्मा. नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो

patrika.com/india

सूखे ने देश के आधे से अधिक राज्यों में अपनी चपेट में ले लिया है। इस सूखे का असर जहां एक ओर जल संकट के रूप में सामने आया है, वहीं दूसरी ओर इस सूखे ने देश में जल विद्युत के उत्पादन को घटा दिया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि सूखे के कारण जल विद्युत उत्पादन घटा है। हालांकि यह भी सही है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित दस राज्यों में उत्पादन अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ है, लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में विद्युत उत्पादन घटा है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार 2015-16 में देश में जल विद्युत का उत्पादन देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश के कारण जल विद्युत का उत्पादन घटा है। मुख्यतया हिमालय क्षेत्र कम बारिश के कारण नदियों का जल प्रवाह कम हो जाने के कारण देश में जल विद्युत का उत्पादन घट गया है।

नदी बेसिन की औसत जल संसाधन क्षमता प्रभावित

केंद्र सरकार ने यह भी स्वीकारा है कि पूर्व में जल की अधिक मात्रा का उपयोग करने वाली व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के कारण देशभर की अधिकांश नदी बेसिन की औसत जल संसाधन क्षमता प्रभावित हुई है। इनमें प्रमुख नदी बेसिन सिंधु, गंगा, गोदावरी , कृष्णा , कावेरी , महानदी , पेन्नार , माही , साबरमती , नर्मदा , ताप्ती , ब्रम्हपुत्र व बराक नदी शामिल हैं। केंद्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग ने बताया कि जल की उपलब्धता और उसके उपयोग का अंतर लगातार बढ़ रहा है। इसे कम करना आवश्यक है। आयोग ने एक आंकलन किया है कि वर्ष 2025 में 8 43 और 2050 में 118 0 बीसीएम जल की वार्षिक आवश्यक होगी। जल की उपलब्धता और उपयोग के अंतर को कम करने के लिए राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर तमाम उपाय कर रही हैं ।

जल संचयन के लिए मास्टर प्लान

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने कुल 8 5 बीसीएम जल संचय करने के लिए देशभर में 1.11 करोड़ वर्षा जल संचयन के लिए मास्टर योजना तैयार की है। इसके माध्यम से घरेलू, औद्योगिक और सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी। यह योजना देश के सभी राज्य सरकारों के पास भेज दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जल के संरक्षण, जल की बर्बादी कम करने, एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों में जल का सामान वितरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन शुरु किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने जल संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा भी तैयार किया है, जिसमें जल के बेहतर प्रबंधन के लिए सिफारिशें की गई हैं। यही नहीं देशभर में आगामी दो सालों के लिए जल क्रांति अभियान भी शुरु किया गया है।

जलाशयों में औसत भंडारण क्षमता कम

देश में जल की अनुमानित औसत वार्षिक उपलब्धता 18 6 9 बीसीएम बिलियन क्यूबिक मीटर है। केंद्रीय जल आयोग देशभर के प्रमुख 91 जलाशयों की निगरानी करता है।

राजस्थान के तीन, छत्तीसगढ़ के दो, पश्चिमी बंगाल के दो, गुजरात के दस, तमिलनाडु के छह जलाशयों में पिछले दस सालों में औसत भंडारण क्षमता लगातार कम हो रही है। जबकि मध्य प्रदेश के छह जलाशयों में औसत भंडारण क्षमता अधिक रही है। जलाशयों में औसत जल भंडारण की क्षमता का उपयोग करने के लिए आयोग ने राज्य सरकारों को एक सलाह जारी की है। इसके अलावा सूखा प्रभावित राज्यों को केंद्र की ओर से आर्थिक मदद भी जारी की है।

पानी को लेकर पलायन

गुजरात में पड़ रही बेतहाशा गर्मी व बांधों के सूखने के चलते लोग तो लोग मवेशियों का भी हाल-बेहाल है। पानी की किल्लत के चलते कच्छ व सौराष्ट्र के मालधारी अपने मवेशियों के साथ घास-चारे व पानी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक समूह अहमदाबाद जिले के साणंद के पास चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे अपना डेरा डाले हुए है।

भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित

भुज में 44 के करीब पहुंचा तापमान

दोपहर को बाजार बंद, सड़कें रहीं सूनी

अहमदाबाद @ पत्रिका

patrika.com/city

प्रदेश में गुरुवार को भीषण गर्मी से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। कच्छ जिले के भुज में तापमान 44 डिग्री सेन्टीग्रेड के करीब पहुंचने से आग उगलती सूरज की किरणों ने जनजीवन पर इतना ज्यादा विपरीत असर छोड़ा कि लोगों को दोपहर में अपने दुकान-प्रतिष्ठान बंद करने पड़े। राज्य में अनेक स्थानों पर सड़कें सूनी हो गई। राज्य में आगामी दिनों में गर्मी का प्रकोप और अधिक होने के आसार जताए गए हैं।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बादलों से घिरे आसमान के बीच निचले स्तर पर चलने वाली पश्चिम-उत्तरीय हवाओं से तापमान 30 से 39 डिग्री तक नीचे आ गया था, इससे गर्मी का असर काफी कम हो गया। इस बीच, बुधवार रात से शुरू हुई उमस भरी गर्मी के बीच गुरुवार को कई स्थलों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेन्टीग्रेड तक पहुंच गया। आसमान से बादल छंटने से सूरज की तीखी धूप की चुभन ने अपना असर दिखाया। इससे राज्य में पूरा दिन जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। विशेष रूप से सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर व मध्य गुजरात में स्थित कच्छ, भुज, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, कंडला, अहमदाबाद, डीसा, गांधीनगर, वड़ोदरा, अमरेली, भावनगर, वल्लभ विद्यानगर में भीषण गर्मी के चलते दोपहर को बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। गर्मी के चलते लोग अपने घर प्रतिष्ठानों से बाहर निकलना टाला। लोगों का आवागमन काफी कम होने से सड़कें सूनी रहीं। बुधवार रात को भी उमस ने लोगों को काफी परेशान किया। कूलर, पंखे जैसे बिजली के उपकरण भी नाकाफी साबित होने से लोग पूरी रात परेशान रहे। हालांकि वातानुकूलित विद्युत उपकरणों की सुविधा वाले नागरिकों को गर्मी से राहत रही। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार से अगले चार पांच दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बरकरार रहेगी। गर्मी में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इससे लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय बाहर आवागमन से टालने की सलाह दी गई है। गर्मी से राहत एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर से सुरक्षा के लिए तरल पदार्थों का अधिकतम सेवन जरूरी बताया गया है।

राज्य में गुरुवार को प्रमुख स्थलों का तापमान इस प्रकार रहा

स्थान	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान
भुज	43.9	24.4
सुरेन्द्र नगर	43.3	25.2
कण्डला	42.5	22.5
अहमदाबाद	42.4	25.8
डीसा	42.4	24.8
राजकोट	41.9	23.5

पाताल से निकालना पड़ता है पानी

RP. 29. P-1

बड़वानी. भीषण सूखे से जूझ रहे बड़वानी में भूजल स्तर पाताल तक पहुंच गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो हालात और गंभीर हैं। इसी की बानगी है बड़वानी से मात्र पांच किमी दूर काचली खोदरी गांव। यहां पानी के लिए महिलाएं-बच्चे जान जोखिम में डालकर तीन किमी दूर पहाड़ों के बीच संकरे 15 फीट गहरे गड्ढे में से पानी ला रहे हैं। फोटो अमजद खान

मोदी सरकार के दो साल पूरा होने का कार्यक्रम रहेगा 'लो प्रोफाइल' | 'देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है' टैगलाइन से बताएंगे उपलब्धियां | 10 राज्यों में है सूखा संकट, केरल को भी प्रभावित घोषित करने की मांग

NBT-29-P-16

सूखे से फीका सरकार का जश्न

Narendra.Mishra
@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : देश में फैली अभूतपूर्व सूखा का असर मोदी सरकार के दो साल के जश्न पर भी दिख सकता है। केंद्र सरकार देश में सूखे की भयावह स्थिति को देखते हुए 2 साल के जश्न को लो प्रोफाइल रखेगी। सूत्रों के अनुसार सरकार के अंदर तय हुआ है कि दो साल की उपलब्धि को लोगों तक सादगी से पहुंचाने के प्रयास होंगे।

सरकार से जुड़े एक मंत्री के अनुसार संभवतः इस बार पीएम या दूसरे मंत्री अलग-अलग जगहों पर रैली न करें। पिछले साल पीएम मोदी ने एक साल पूरा होने के मौके पर यूपी के बरेली में एक बड़ी रैली की थी। दरअसल अभी देश की एक चौथाई आबादी सूखे की चपेट में है और अगले एक महीने तक इसमें कोई खास सुधार होने की उम्मीद भी नही है।

अब तक के कार्यक्रम के अनुसार जरा मुस्करा दो अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धि को आईबी मिनिस्ट्री अलग-अलग माध्यम से दिखाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी सभी मंत्रियों को डिनर भी दे सकते हैं। साथ ही सरकार 'देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है' टैगलाइन के साथ भी अपनी उपलब्धियों को देश तक पहुंचाएगी।

NBT

यह कोई समुद्र तट नहीं, नैनीताल की झील है, जो बड़ी तेजी से सूख रही है।

बीयर कंपनियों को कम सप्लाई : हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीयर कंपनियों को पानी की सप्लाई कम करने को कहा है। इससे प्रॉडक्शन कम हो सकता है। औरगांबाद में बीयर की 16 कंपनियों को 60 फीसदी कम पानी सप्लाई करने को कहा है। यह कटौती 27 अप्रैल से 10 जून तक होगी। 1 लीटर बीयर बनाने में करीब 5 लीटर पानी लगता है।

मराठवाड़ा में 65 किसानों ने जान दी

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में कम बारिश होने के कारण सूखा और फसल के नुकसान के चलते अप्रैल में 65 किसानों ने खुदकुशी की है। सबसे ज्यादा खुदकुशी बीड में की गई हैं। क्षेत्र का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला लातूर है।

100 करोड़ का स्टील प्लांट ठप

लातूर में 300 टन स्टील रोजाना प्रड्यूस करने वाला 100 करोड़ का एक स्टील प्लांट पानी न होने की वजह से बंद हो गया। प्लांट को रोजना 3 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती थी। यहां काम करने वाले 1700 लोग (ज्यादातर बिहार से) बेरोजगार हो गए।

जायजा लेने जाएंगी तकनीकी टीमें

■ प्रस, नई दिल्ली : सरकार ने देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के हालात का जायजा लेने के लिए तकनीकी टीमों को वहां भेजने का फैसला लिया है। ये जल प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों का लेखाजोखा और वहां पानी की कमी और रीचार्जिंग के स्तर का पता लगाएंगीं। इसके साथ ही ये ऐसे उपाय सुझाएंगे, जिनसे पानी की कमी का स्थायी समाधान हो सके। जून में जायजा लेने जाने वाली इन टीमों को दो हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देनी है। दूसरी ओर कम बारिश के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हालात को देखते हुए प्रदेश के 13 में से पांच जिले सूखाग्रस्त घोषित होंगे।

आप (मोदी जी) सूखा मुक्त भारत करिए, अपने आप देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। सूखा 50 साल की देन है।

– संजय राउत, शिवसेना प्रवक्ता

देश के दस राज्यों में पेयजल का संकट

नई दिल्ली/लखनऊ/देहरादून | हिटी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि इस समय देश के 10 राज्य सूखे की स्थिति के कारण गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। प्रभावित राज्यों में उत्तरप्रदेश, ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं।

लोकसभा में पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि इन 10 राज्यों के अलावा बिहार, गुजरात और हरियाणा के भी कुछ हिस्से जल संकट है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सूखा समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल आवंटन का दो प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

वहीं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर में गिरावट आई है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार 47 प्रतिशत कुओं के भूजल स्तर में गिरावट आई है।

यूपी के 39 जिलों में टैंकरों से पानी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में 692 और बुंदेलखंड में 402 टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। कार्यवाहक मुख्य सचिव प्रवीर कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने 867 करोड़ रुपये का किसानों के खाते में अभियान चलाकर एक सप्ताह में वितरण करने के निर्देश भी दिए हैं।

सूखे से प्रभावित जिलों में राहत की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने बुंदेलखंड के मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सूखे से प्रभावित नागरिकों की मदद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

H-29
P-12

हेमा मालिनी ने
संकट का मुद्दा उ

नई दिल्ली, (भाषा): सिने तारिका और सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा में जल संरक्षण, नदियों को

स्वच्छ बनाने और उन्हें
पूर्व प्रधानमंत्री अटल
वाजपेयी के सपने को पूरा
मांग की।

हेमा मालिनी ने लो
शून्यकाल में देश के ब
पेयजल के संकट को उठा
संरक्षण के दीर्घकालिक

ocumented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

पानी का बेजा इस्तेमाल करना हराम

129
P-12

उलेमाओं की पहल

- दारुल उलूम देवबंद व खानकाह ए-नियाजिया ने की अपील
- सूखे से निजात पाने के लिए विशेष नमाज अदा करने को कहा

मेरठ | हिन्दुस्तान टीम

पानी बचाने और उसकी बर्बादी रोकने के लिए हिन्दुस्तान की मुहिम बिन पानी सब सून में धार्मिक गुरु भी आगे आ गए हैं। वहीं, दारुल उलूम देवबंद ने तो मुसलमानों से अपील की है कि वह सूखे से निजात पाने को विशेष नमाज अदा करें। देवबंद के साथ ही बरेली के दोनों मरकज ने भी इसी तरह की अपील जारी की है। शुक्रवार को तमाम जगहों पर तकरीर और खास दुआएं होंगी।

दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि पानी अल्लाह की दी गई वो नियामत है जिसका बेजा इस्तेमाल करना भी हराम है। उन्होंने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बारिश के लिए विशेष नमाज (नमाज-ए-इसतसका) अदा करने और पूरे देश में हर नमाज के बाद पानी के लिए दुआएं करने की अपील की।

शरीयत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसलाम में तो जंग के वक्त भी पानी और पेड़ों को बचाने का हुक्म दिया गया है। जल की बर्बादी रोकने को चलाई जा रही हिन्दुस्तान अभियान की मुहिम 'बिन पानी सब सून' को दरगाह आला हजरत की संस्था जमात रजा ए मुस्तफा का भी साथ मिला है। जमात रजा ए मुस्तफा के अध्यक्ष शहर काजी मोहम्मद असजद रजा खां कादरी ने कहा कि इस्लाम में पानी की फिजूलखर्ची से बचने का हुक्म है।

खानकाह-ए-नियाजिया बरेली के प्रबंधक शब्बू मियां नियाजी ने कहा कि हिन्दुस्तान अखबार की मुहिम बिन पानी सब सून में खानकाह-ए-नियाजिया साथ है। नियाजी ने कहा, जलसंकट को देखते हुए पानी की बूंद-बूंद बचाना हम सबका सामाजिक और मजहबी फर्ज है।